अध्याय-3

गंगा की स्वच्छता के लिए सहायक पहल: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वानिकी गतिविधियाँ तथा घाट एवं श्मशान घाट

अध्याय-3

गंगा की स्वच्छता के लिए सहायक पहल: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वानिकी गतिविधियाँ तथा घाट एवं श्मशान घाट

सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से अपर्याप्त जन जागरूकता के कारण विभिन्न स्थानों में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस एम सी जी) द्वारा निर्मित श्मशान घाट अधिकतर अप्रयुक्त रहे। नियोजित व्यय का मात्र 16 *प्रतिशत* ही कार्यान्वित किए जाने के साथ वन संबंधी गतिविधियों की प्रगति अत्यंत सीमित रही। गंगा नदी पर बसे नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस डबल्यू एम) अपर्याप्त प्रबंधन प्रथाओं से ग्रस्त था, क्योंकि अपशिष्ट को मुख्य रूप से नदी की ढलानों पर फेंक दिया जाता था या उचित प्रसंस्करण के बजाय जलाकर निपटाया जाता था, जिसके कारण यह नदी में वापस बह जाता था।

3.1 गंगा की स्वच्छता के लिए सहायक पहल

नगरपालिका के सीवेज के शोधन हेतु सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना के अतिरिक्त, नदी प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कई सहायक पहल की गई हैं। जिनमें शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) में एस डबल्यू एम को सुदृढ़ करना, घाटों एवं श्मशान घाटों का निर्माण तथा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे वानिकी गतिविधियाँ शामिल हैं। ये पूरक प्रयास गंगा नदी के प्रदूषण को परोक्ष रूप से कम करने में योगदान देते हैं।

3.2 घाट एवं श्मशान घाट

स्नान घाट एवं श्मशान घाट मानव और नदी के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन काल से ही नदी किनारों का उपयोग पूजा-अर्चना एवं मृतकों के दाह-संस्कार हेतु किया जाता रहा है। घाटों एवं श्मशान घाटों का विकास नदी किनारों की स्वच्छता बनाए रखने तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने में सहायक होता है। यह गंगा नदी में अधजले शवों के विसर्जन को रोकने में भी मदद करता है और 'जन-नदी संबंध' को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन एम सी जी) द्वारा ₹ 328.59 करोड़ की लागत से 31 घाट और 28 श्मशान घाट स्वीकृत किए गए। लेखापरीक्षा ने ₹ 88.62 करोड़ की कुल लागत वाले 11 घाटों और 15 श्मशान घाटों की जाँच की। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

3.2.1 माँग एवं आवश्यकता विश्लेषण के बिना किए गए निर्माण के कारण अप्रयुक्त श्मशान घाट

किसी भी परियोजना/सेवा हेतु सार्वजनिक धन व्यय करने के लिए स्थानीय जनता की माँग सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होता है। स्थानीय माँग से न केवल निर्मित परिसंपत्तियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा उनका अनुरक्षण भी किया जाता है। एन एम सी जी द्वारा यह पाया गया (अगस्त 2017) कि कई प्रकरणों में घाट एवं श्मशान घाट या तो आवश्यकता आधारित नहीं थे या वह आधिक्य डिज़ाइन किए गए थे। अतः एस एम सी जी उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया कि इन कार्यों को लेते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए:

- घाट एवं श्मशान घाट के विकास कार्य स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एवं स्थानीय निकायों से परामर्श के उपरांत ही लिए जाएं।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस एम सी जी उत्तराखण्ड स्थानीय निकायों से परामर्श करें एवं भविष्य की संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व परियोजना समर्थन अवधि के बाद ओ एवं एम का दायित्व लेने हेतु यू एल बी का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए, साथ ही सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं स्वीकृतियाँ भी ली जाएं।

एन एम सी जी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, श्मशान घाटों का निर्माण स्थानीय जनता की माँग या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का मूल्यांकन किए बिना किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 11 श्मशान घाटों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि इनका न तो स्थानीय जनता द्वारा उपयोग किया गया और न ही उन्हें जिन स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया गया था, उनके द्वारा इनका अनुरक्षण किया गया।

निर्मित श्मशान घाटों की स्थिति नीचे **तालिका-3.1** में दी गई है:

तालिका-3.1: संयुक्त भौतिक निरीक्षण के अनुसार श्मशान घाटों की स्थिति

क्र. सं.	स्थान	क्या स्थानीय जनता द्वारा माँग की गई	उपयोग किया गया या नहीं	यदि अप्रयुक्त है, तो चिताएं कहाँ जलाई जाती हैं	अनुरक्षित किया गया या नहीं	पूर्ण होने की तिथि
1.	श्मशान घाट, चमोली	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	मई 2019
2.	श्मशान घाट, नंदप्रयाग	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	जनवरी 2019

क्र. सं.	स्थान	क्या स्थानीय जनता द्वारा माँग की गई	उपयोग किया गया या नहीं	यदि अप्रयुक्त है, तो चिताएं कहाँ जलाई जाती हैं	अनुरक्षित किया गया या नहीं	पूर्ण होने की तिथि
3.	श्मशान घाट, कर्णप्रयाग	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	मार्च 2019
4.	श्मशान घाट-2, पोखरी पुल, कर्णप्रयाग	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	मार्च 2019
5.	घोलतीर श्मशान घाट, रुद्रप्रयाग	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	मार्च 2019
6.	कोटेश्वर श्मशान घाट, टिहरी	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	नवंबर 2018
7.	गौचर श्मशान घाट	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	मार्च 2019
8.	केदार श्मशान घाट, उत्तरकाशी	नहीं	बहुत कम उपयोग किया गया	कुछ चिताएं नदी के तल में एवं कुछ श्मशान घाट में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	फरवरी 2019
9.	हीना श्मशान घाट, उत्तरकाशी	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	फरवरी 2019
10.	डुंडा श्मशान घाट, उत्तरकाशी	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	दिसंबर 2018
11.	उमरकोट श्मशान घाट, कर्णप्रयाग	नहीं	उपयोग नहीं किया गया	चिताएं नदी के तल में जलाई जाती हैं	अनुरक्षित नहीं किया गया	जनवरी 2019

निम्नलिखित चित्र भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हैं:

चित्र-3.1: अव्यवस्थित और क्षतिग्रस्त श्मशान घाट संख्या 2, कर्णप्रयाग (दिनांक: 13 दिसंबर 2023)

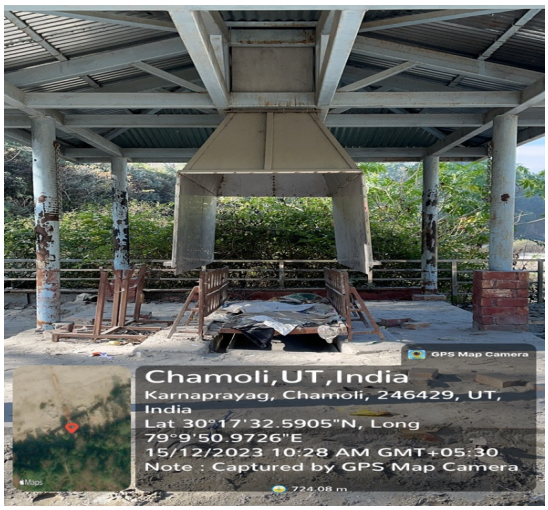

चित्र-3.2: अप्रयुक्त एवं अव्यवस्थित श्मशान घाट, गौचर

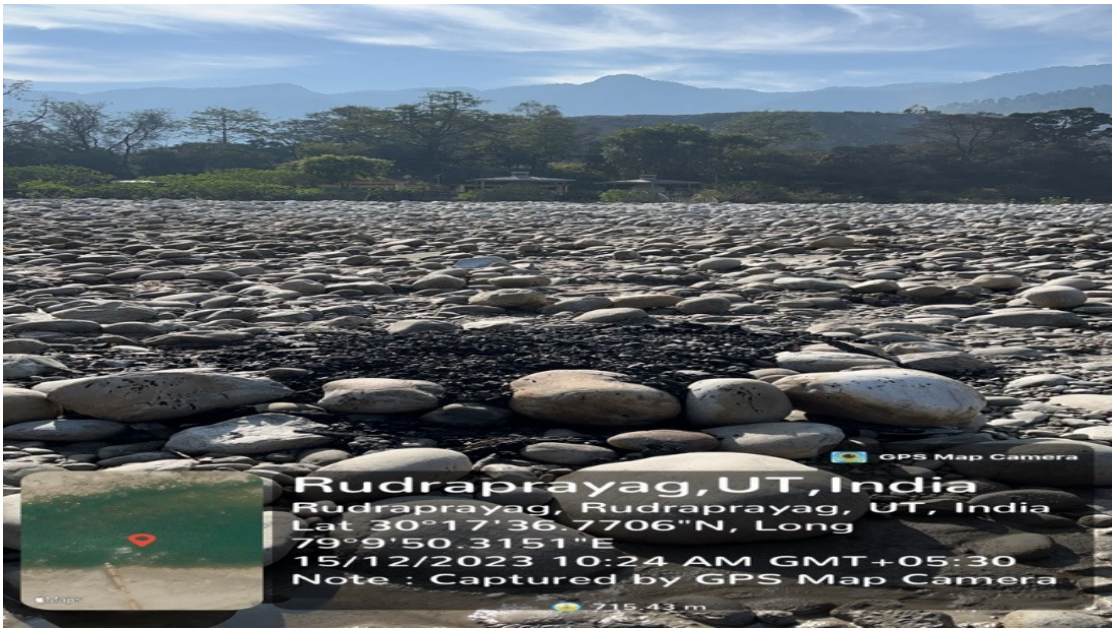

चित्र-3.3: गौचर में नदी के किनारे चिता के अवशेष

राज्य सरकार ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2024) और अवगत कराया कि संबंधित यू एल बी द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों (मई 2024) के माध्यम से जनता को उपलब्ध श्मशान घाट का उपयोग करने और नदी के तलों में चिता जलाने की प्रथा को छोड़ने के लिए संवेदनशील बनाया जा रहा था।

3.3 गंगा नदी के लिए वानिकी गतिविधियाँ

गंगा के लिए वानिकी गतिविधियाँ नमामि गंगे कार्यक्रम का एक उप-हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी जलग्रहण क्षेत्र के लाभ के लिए स्थायी वन प्रबंधन है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने गंगा नदी के संपूर्ण आवाह क्षेत्र में किए जाने वाले आवश्यक गतिविधियों (मुख्य रूप से वृक्षारोपण) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार की थी। इस योजना को 2016-17 से 2020-21 के दौरान पूरा किया जाना था।

परियोजना प्रबंधन इकाई-गंगा के लिए वानिकी गतिविधियाँ, वन विभाग उत्तराखण्ड की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

3.3.1 वानिकी गतिविधियों की अल्प प्रगति

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुमोदित डी पी आर में 2016-17 से 2020-21 की योजना अवधि के दौरान उत्तराखण्ड में 54,855.43 हेक्टेयर[1] में वृक्षारोपण के लिए ₹ 885.91 करोड़ के व्यय की योजना बनाई थी। हालांकि, परियोजना प्रबंधन इकाई,

[1] डी पी आर के अनुसार अनुमानित क्षेत्र: प्राकृतिक परिदृश्य (30,302.50 हेक्टेयर) + कृषि परिदृश्य (15,180.00 हेक्टेयर) शहरी परिदृश्य (1,406.08 हेक्टेयर) + संरक्षण गतिविधियाँ (7,966.85 हेक्टेयर)।

गंगा के लिए वानिकी गतिविधियाँ उत्तराखण्ड द्वारा एन एम सी जी के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना (ए पी ओ) में बहुत कम राशि का प्रस्ताव किया। इसने योजना के अंतर्गत व्यय को मूल रूप से नियोजित वित्तीय लक्ष्यों के केवल 16 *प्रतिशत* तक सीमित कर दिया गया, जिसका ब्यौरा नीचे **तालिका-3.2** में दिया गया है:

तालिका-3.2: अनुमोदित डी पी आर के अनुसार लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण

(सभी राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	डी पी आर के अनुसार नियोजित व्यय	प्रस्तावित एवं अनुमोदित ए पी ओ	व्यय	नियोजित व्यय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता
2016-17	358.91	15.93	15.80	4.40
2017-18	162.57	19.57	19.03	11.71
2018-19	223.97	31.77	30.56	13.64
2019-20	58.70	19.19	16.28	27.73
2020-21	81.76	39.36	36.65	44.83
2021-22	-	26.39	18.38	-
2022-23	-	16.92	7.57	-
योग	***885.91***	***169.13***	***144.27***	***16.28***

स्रोत: परियोजना प्रबंधन इकाई, गंगा के लिए वानिकी गतिविधियाँ, वन विभाग उत्तराखंड।

नियोजित व्यय की तुलना में ए पी ओ और वित्तीय प्रगति कम होने के कारण भौतिक लक्ष्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। प्राकृतिक परिदृश्य (योजना का मुख्य घटक), कृषि परिदृश्य, शहरी परिदृश्य और संरक्षण गतिविधियों के अंतर्गत भौतिक प्रगति नियोजित लक्ष्यों का केवल 34 *प्रतिशत*[2], 9 *प्रतिशत*[3], 6 *प्रतिशत*[4] और 14 *प्रतिशत*[5] ही प्राप्त की जा सकी। यह योजना वन अनुसंधान संस्थान द्वारा योजित और एन एम सी जी द्वारा अनुमोदित की गई अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मई 2024) कि एन एम सी जी द्वारा जारी कुल धनराशि डी पी आर में लक्ष्यों से काफी कम थी। तथापि, यह अवगत कराया गया कि कैम्पा और अन्य वानिकी योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त वृक्षारोपण की योजना बनाई गई थी।

---

[2] प्राकृतिक परिदृश्य: आच्छादित क्षेत्र: (10,416.70 हेक्टेयर)/डी पी आर के अनुसार अनुमानित क्षेत्र: (30,302.50 हेक्टेयर)।

[3] कृषि परिदृश्य: आच्छादित क्षेत्र: (1,412.84 हेक्टेयर)/डी पी आर के अनुसार अनुमानित क्षेत्र: (15,180.00 हेक्टेयर)।

[4] शहरी परिदृश्य: आच्छादित क्षेत्र: (90.60 हेक्टेयर)/डी पी आर के अनुसार अनुमानित क्षेत्र: (1,406.08 हेक्टेयर)।

[5] संरक्षण गतिविधि: आच्छादित क्षेत्र: (1,128.00 हेक्टेयर)/डी पी आर के अनुसार अनुमानित क्षेत्र: (7,966.85 हेक्टेयर)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कैम्पा और अन्य वानिकी योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण के विशिष्ट उद्देश्य हैं, जबकि वानिकी गतिविधियों के अंतर्गत नियोजित वृक्षारोपण की विशिष्ट विशेषताएं गंगा पुनरूद्धार के अनुरूप हैं। इसलिए, गंगा के लिए वानिकी गतिविधियों में कमी की भरपाई अन्य वृक्षारोपण पहलों द्वारा नहीं की जा सकती है।

3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट, या तो लोगों द्वारा जानबूझकर या मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे जल निकायों में बह जाता है। पानी में, बड़ी मात्रा में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पानी से बहुत अधिक ऑक्सीजन ले सकता है, जिससे मछली और अन्य जलीय जीवों को बीमारी और उनकी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन। गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री नदियों के माध्यम से तैरती है, पानी के मुक्त प्रवाह में ब्लॉक बनाती है और धीरे-धीरे अपने हानिकारक रसायनों को पानी में ही छोड़ देती है। जलीय जीव अक्सर गलती से इन सामग्रियों को खा जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए, गंगा के प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य गंगा समिति अपनी बैठकों में एस डबल्यू एम की स्थिति की निगरानी करती है।

एस डबल्यू एम नियम, 2016 यू एल बी और जनगणना नगरों में ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के बारे में सभी व्यवस्थाओं को चित्रित करता है। उक्त नियम के नियम 16 के उपबंध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी) को स्थानीय निकायों के माध्यम से इन नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं।

लेखापरीक्षा ने ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में विभिन्न कमियों को देखा जैसा कि नीचे बताया गया है:

3.4.1 ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्राधिकार का अभाव

एस डबल्यू एम नियम, 2016 के नियम 15 में प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकरण और पंचायत अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए एस पी सी बी से प्राधिकार[6] प्राप्त करेंगे, यदि अपशिष्ट की मात्रा सैनिटरी लैंडफिल सहित प्रति दिन पांच मीट्रिक टन से अधिक है। नियम 16 में एस पी सी बी को अन्य शर्तों सहित नियमों की अनुसूची-I और II में यथा वीनिर्दिष्ट अनुपालन मानदंड और

[6] प्राधिकार का अर्थ है एस पी सी बी द्वारा किसी सुविधा के संचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार किसी अन्य अभिकरण को दी गई अनुमति।

पर्यावरणीय मानकों को निर्धारित करते हुए आवेदन की 60 दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकार प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू के पी सी बी) के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2022-23 के दौरान राज्य में 102 यू एल बी थे। इनमें से 44 यू एल बी पांच टन प्रतिदिन या अधिक मात्रा में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन कर रही थीं। तथापि, उनमें से कोई भी ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधाओं के लिए यू के पी सी बी से प्राधिकार प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। एस डबल्यू एम नियम, 2016 के प्रभावी होने के बाद से वर्षवार स्थिति नीचे **तालिका-3.3** में दी गई है:

तालिका-3.3: ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान की सुविधाओं के लिए यू के पी सी बी से प्राधिकार की स्थिति

वर्ष	प्राप्त प्राधिकार आवेदनों की संख्या	दिए गए प्राधिकारों की संख्या
2017-18	06	0
2018-19	24	0
2019-20	18	0
2020-21	08	0
2021-22	20	0
2022-23	02	0

स्रोत: उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

यू के पी सी बी ने बताया कि प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाए गए। यह इंगित करता है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एस डबल्यू एम नियम, 2016 द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार नहीं था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राज्य गंगा समिति ने इस तथ्य के बावजूद कि वे नदी में संभावित रूप से प्रदूषण बढ़ा सकते हैं, ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के प्राधिकारों की स्थिति के बारे में कभी पूछताछ नहीं की।

राज्य सरकार ने (मई 2024) तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के प्राधिकारों के संबंध में शहरी विकास विभाग निदेशालय द्वारा जनवरी 2024 में सभी यू एल बी को निर्देश जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं बिना उचित प्राधिकार के संचालित होती रहीं, नियमों के लागू होने के सात वर्ष बाद भी यू के पी सी बी, एस डबल्यू एम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाया।

3.4.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जमीनी रिपोर्ट

गंगा तटवर्ती शहरों में एस डबल्यू एम की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने संयुक्त रूप से 10 पर्वतीय नगरों[7] में एस डबल्यू एम सुविधाओं/ डंपिंग ग्राउंड का संयुक्त निरीक्षण किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट को नदी की ढलानों पर अंधाधुंध फेंका जा रहा था या जलाकर निपटाया जा रहा था। परिणामस्वरूप, सभी ठोस अपशिष्ट या तो राख के रूप में समाप्त हो गए या बारिश के दौरान नदी में बह जाने का खतरा था। निम्न चित्र इस मुद्दे के लिए साक्ष्य के रूप में काम करते हैं:

चित्र-3.4: अलकनंदा की ढलान एवं लीगेसी अपशिष्ट पर अपशिष्ट फेंका एवं जलाया गया-जोशीमठ

चित्र-3.5: अलकनंदा के बल्खिला गदेरे की ढलान पर अपशिष्ट फेंका एवं जलाया गया-चमोली

चित्र-3.6: नंदप्रयाग में अलकनंदा की ढलान पर फेंका गया अपशिष्ट

चित्र-3.7: नंदप्रयाग डंपिंग ग्राउंड में नियमित रूप से अपशिष्ट जलाया जाता था

[7] जोशीमठ, गोपेश्वर - चमोली, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, टिहरी, गौचर, उत्तरकाशी एवं देवप्रयाग।

चित्र-3.8: अलकनंदा के तट पर कर्णप्रयाग में डंपिंग ग्राउंड (दिनांक: 13 दिसंबर 2023)

चित्र-3.9: अलकनंदा के तट पर श्रीनगर में विशाल कूड़े का ढेर (दिनांक: 5 नवंबर 2023)

चित्र - 3.10: रुद्रप्रयाग में अलकनंदा की ढलान पर कूड़े का विशाल ढेर

छः नगरों के उपरोक्त चित्रों में दर्शाई गई स्थिति, टिहरी, गौचर और उत्तरकाशी में भी पाई गई थी। देवप्रयाग एक अपवाद था जहाँ कीर्तिनगर में नदी से दूर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थित थी।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि गंगा नगरों में अधिकांश ठोस अपशिष्ट डंपिंग ग्राउंड अनुपयुक्त स्थानों पर स्थित थे, अधिकांश नदी के किनारों के पास थे। इससे बरसात के मौसम में अपशिष्ट नदी में बह जाने की संभावना बढ़ जाती है। इन स्थलों पर ठोस अपशिष्ट जलाना भी एक आम बात थी। सात वर्ष पहले एस डबल्यू एम नियम बनने के बावजूद एस डबल्यू एम की व्यवस्था अपर्याप्त रही। राज्य गंगा समिति और संबन्धित जिला गंगा समितियों ने ठोस अपशिष्ट निपटान व्यवस्थाओं की निराशाजनक स्थिति का समाधान नहीं किया।

राज्य सरकार ने (मई 2024) तथ्यों को स्वीकार करते हुए पुष्टि की, कि सभी यू एल बी को लीगेसी अपशिष्ट डंप पर आग की घटनाओं को रोकने एवं ठोस अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय दंड लगाने जैसी कार्रवाई की गयी है।

3.5 अनुशंसाएं

1. ***श्मशान घाटों के उपयोग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की पहल को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।***
2. ***समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट का दक्षतापूर्ण प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है एवं इसके लिए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तत्काल विनियामक प्राधिकार प्राप्त किया जा सकता है।***